

फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

(प्लाट न0-100, फेस-1, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा)

रेफरन्स न0

दिनांक : 31-3-06

सेवा में,

माननीय श्रमायुक्त महोदया,
श्रम विभाग हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

मै0 फैशन एक्सप्रैस 100, फेस-1, उद्योग विहार, गुडगांव के प्रबंधकों
द्वारा दीपावली बोनस वितरण के समय अपनाई गई भेदभाव नीति के
कारण संस्थान में तनाव ग्रस्त हालत बारे व Sexual Harrasment बारे
शिकायत पर रिपोर्ट ।

मान्यवर मैडम,

सादर तथा विनम्र निवेदन है कि :-

1. यह कि आपके कार्यालय से पत्र संख्या 7808 दिनांक 06.03.2006 द्वारा जा कि उपरोक्त विषय माननीय उप श्रमायुक्त, गुडगांव को लिखा गया है—
इस पत्र में आपने बोनस विषय में धारा 2 (k) के अन्तर्गत यूनियन को विधिवत मांग पत्र देने का परामर्श देने हेतु कहा है।
2. यह कि हमें खेदपूर्वक निवेदन करना पड़ रहा है कि आपके उपरोक्त पत्र में लिखी गई बात किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है—क्योंकि श्रमिकों ने माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी को समझौता वार्ता के दौरान यह निवेदन रिकार्ड करा दिया था कि यूनियन/श्रमिकों की शिकायत को ही धारा 2 (k) के अन्तर्गत औद्योगिक माना जावे और इसी पर आगामी कार्यवाही की जावे। माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी तथा उप श्रमायुक्त गुडगांव, दोनों अधिकारियों श्रमिकों के इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए छानबीन उपरान्त आपके कार्यालय को यह सिफारिश भिजवायी है कि विवाद को न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायलय में भेज दिया जावे ।

Veena/3-4/06

रामेश्वरमिं

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

(प्लाट नं 100, फेस-1, उघोग विहार, गुडगाँव, हरियाणा)

टेकरन्स नं 0

दिनांक :

2

3. यह कि उपरोक्त हालात तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा निवेदन है कि मामले में अनावश्यक विलम्ब को दूर करते हुए विवाद को शीघ्र - अतिशीघ्र न्याय निर्णय हेतु औद्योगिक न्यायधिकरण को भिजवाने के कृपा करें क्योंकि श्रमिकों में प्रबंधकों की बोनस अदायगी बारे अपनाई गई भेदभाव पूर्ण नीति के कारण भारी रोष और अशांति है। यूनियन द्वारा प्रबंधकों के विरुद्ध अभी तक किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही का निर्णय नहीं लिया गया है। यदि मामले को न्याय निर्णय हेतु भेजने में विलंब किया गया तो श्रमिकों को मजबूरीवश प्रबंधकों के विरुद्ध हड़ताल सहित किसी भी सीधी कार्यवाही का निर्णय लेना पड़ सकता है।
- हम आशा करते हैं कि आप उपरोक्त किसी भी अनहोनी की स्थिति पैदा होने नहीं देंगे और मामले को न्याय निर्णय हेतु भेजने को निर्णय लेने की तत्काल कृपा करेंगे। श्रम विभाग यदि चाहे तो मुख्यालय स्तर पर दोनों पक्षों को समझौता वार्ता हेतु पुनः अन्तिम बैठक रखने के लिए सोच सकता है ताकि विवाद में आपसी सहमति की स्थिति पैदा होती है उसके लिये आप प्रयास कर सकें।

निवेदक

२१/१९८५ क्र. ३३

(सतबीर सिंह)
प्रधान

प्रति :- 1. माननीय वित्तायुक्त तथा
सचिव महोदया, हरियाणा सरकार
चण्डीगढ़।

2. L.O., Gurgaon.

✓ 3. D.L.C., Gurgaon.

Reed

1/1
5/6/06
10 D.L.C.
Chandigarh